DR. DASARI NARAYAN RAO: Sir, this is a proposal moved by the Coal India Limited and the proposal has reached the Government, and the Government has to consider the proposal. When it comes to the Govenrment, we will elaborately discuss about it and then I will get back to the Member.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, it is about the merger of BCCL and ECL with Coal India Limited. Proposals are given by a number of agencies to the Government. I would like to know whether that will be initiated first before going abroad. That is the first part of my question.

DR. DASARI NARAYAN RAO: Sir, at present, we don't have any such proposal. The hon. Member is very much concerned about it. We will look into it.

श्री अबू आसिम आजमी: चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किस देश से कितना कोयला इम्पोर्ट किया जा रहा है, क्या हर साल इसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है और इस पर कुल कितना खर्चा आ रहा है?

†[شری ابوعاصم اعظمی: چیئرمین صاحب، میں آپ کے ماوسیلہ سے منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس دیش میں کتنا کوئلہ امپورٹ کیا جارہا ہے؟ کیا ہر سال اس کی ماترا بڑھتی جارہی ہے اور اس پر کتنا خرچ آرہا ہے؟]

DR. DASARI NARAYAN RAO: Sir, most probably, we are depending on imported coking coal. Coking coal production is very less. We get 23.8 million tonnes of coking coal from the public sector and 6.3 million tonnes from the private sector. The total comes to 30 million tonnes. Our requirement is 45 million tonnes. So, there is no other go except to import.

Growth of KVI sector

*426. SHRI S.P.M. SYED KHAN:††
DR. K. MALAISAMY:

Will the Minister of AGRO AND RURAL INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether enough priority and importance are given to the growth and development of Khadi and Village Industries sector in the wake of its vital role in rural economy and employment;

† [ ] Transliteration in Urdu Script.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Shri S.P.M. Syed Khan.

(b) if so, what is the budgetary support given under Plan and non-Plan and the flow of institutional finance during the last three years as against its requirement; and

(c) what are the core reasons for the decline and fall of this sector after its golden age for about three decades during 50s to 80s?

THE MINISTER OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES (SHRI MAHAVIR PRASAD): (a) to (c) A statement is placed on the Table of the Sabha.

(a) Yes, Sir.

(b) While the khadi component of the Khadi and Village Industries (KVI) sector is funded entirely through the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), village industries are set up both through the KVIC under the Rural Employment Generation Programme (REGP) and under the Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY), a scheme for providing self-employment opportunities to educated unemployed youth (with approximately 50 per cent of the units being in rural areas). Both REGP and PMRY are credit-linked subsidy schemes, credit being provided by banks and subsidy by the Central Government. The budgetary support given by the Government for the growth and development of the KVI sector under plan and non-plan heads and the loans advanced by banks under (i) the REGP, (ii) the PMRY and (iii) the Interest Subsidy Eligibility Certificate (ISEC) Scheme (for providing bank loans to khadi and polyvastra units at subsidised rates of interest) during the last three years, are as under:

(Rs. in crore)

Year	Budgetary support provided by the Government			Loans provided by banks		
	Plan	Non-Plan	Total	REGP	PMRY	ISEC
2002-03	508.65	63.36	592.01	484.28	1198.48	329.73
2003-04	591.61	60.75	652.36	664.36	1367.55	362.70
2004-05	679.18	83.90	763.08	731.00	1460.25	278.47

(c) There has been significant growth in the KVI sector over the years. The value of production, which was Rs. 16.47 crore (khadi-Rs. 5.54 crore and village industries - Rs. 10.93 crore) in the year 1955-56, has increased to Rs. 10920.43 crore (khadi — Rs. 461.54 crore and village industries — Rs. 10458.89 crore) in 2004-05. The growth in the VI sector has been steady. While there has decline in the production and sales of khadi and

khadi products during 1998-99 to 2001-02, these have improved in the last three years (2002-03 to 2004-05).

The problems faced by the KVI sector include those on account of obsolete technology, inconsistent quality of products, products not being in tune with the market demand, inadequate and delayed credit, management deficiencies, etc.

SHRI S.P.M. SYED KHAN: I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, what was the exact reason for decline in production and sale during the particular period from 1998 to 2002, while it was on the increase in all other periods.

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो एक पीरियड में ग्रामीण उद्योग और खादी के बारे में पूछा है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 1997-98 में खादी और ग्रामीण उद्योग विभाग की तरफ से हमने लगभग 14 लाख रोजगार दिए थे, लेकिन धीरे-धीरे कम होते-होते 2004-05 में वे 8.6 लाख हो गए। श्रीमन्, इस बीच में हमने कोशिश की और धीरे-धीरे 2004-05 से फिर इसमें बढ़ोत्तरी शुरू हो गई है। इसमें बढ़ोत्तरी शुरू होने के कारण हैं कि हमने विशेषकर कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं, जिनके आधार पर खादी और ग्रामोद्योग आगे बढ़ा है। इसमें हमारे जो दो कार्यक्रम चलते हैं, वे हैं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) और आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आज पूरे देश में (REGP) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के आधार पर हमने 2,09,750 यूनिट स्थापित की हैं और साथ ही साथ इसमें 1,372 करोड़ रुपए मार्जिन मनी हमने दी है और 28 लाख के लगभग इसमें नए रोजगार सृजित हुए हैं। इस तरह से हम धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं, हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार यह कोशिश कर रही है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

SHRI S.P.M. SYED KHAN: Sir, is it true that there are a number of private outlets which are selling fake khadi products? If so, what mechanism do they have to check this malpractice and set it right?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी तरफ से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसके लिए हमने कई प्रकार की कार्य योजनाएं चलाई हैं। जैसे खादी के विषय में खादी रिबेट स्कीम हमने चालू की है, खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना हमने शुरू की है, ब्याज सब्सिडी पात्रता स्कीम हमने शुरू की है, उत्पाद, विकास खादी और ग्रामोद्योग हमने चलाना शुरू किया है ताकि इसको पसंद करके आगे हमें बढ़ें। उसी प्रकार से भी ग्रोमोद्योग में हमने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया है।...(व्यवधान)

श्री सभापति: सारे कागज इनके पास भेज दीजिए, वे देख लेंगे।

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is conceded that the prime objective of the Khadi and Village Industries sector is to play a vital role in providing employment, uplifting the rural economy and making it self-reliant by utilising the local talent and local raw material. As such, it is helping the rural sector as a whole. If it is so, is it not the prime duty of the Government to see that this sector is given full assistance? The allocation made to the Department by way of budgetary support and through other schemes is very minimal. I would like to know whether the hon. Minister would make all out efforts to see that this Department is provided more and more allocations. Will he make efforts to get separate allocation for this Department because the allocation has been made for the Ministry as a whole?

श्री महावीर प्रसाद: आदरणीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत ही मौलिक है।

श्री सभापति: आप यह कह कर संकट खड़ा कर देते हैं।

श्री महावीर प्रसाद: मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खादी का हमारी राष्ट्रीय जगत में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे ग्रामीण उद्योग का और इसको हम काफी मजबूत करने के लिए बहुत सी योजनाएं इसमें भी चला रहे हैं, जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं। इसके बढ़ोत्तरी के लिए निर्यात बाजार संवर्द्धन की बात कर रहे हैं, घरेलू बाजार के संवर्द्धन की बात कर रहे हैं, उत्पादन और संरचना के विकास की बात कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य महोदय की यह मांग है कि अलग से हम इसके लिए बजट की व्यवस्था करें...(व्यवधान)

श्री सभापति: इसके लिए विचार करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद: विचार तो अभी करेंगे जो हमारा ए॰आर॰आई॰ डिपार्टमेंट है, जो हमारा एक हिस्सा है, उस पर हम अलग से विचार करेंगे कि उस पर क्या हो सकता है इसमें।

श्री सभापति: ठीक है। Shrimati S.G. Indira.

DR. K. MALAISAMY: Sir, my second supplementary is...

MR. CHAIRMAN: No second supplementary. Please take your seat.

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is very important.

MR. CHAIRMAN: Please take your seat. You have already put your question. That is enough.

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is very important.

MR. CHAIRMAN: नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। Wait for the next session.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, it has been mentioned in the reply that this scheme is for providing self-employment opportunities to unemployed educated youth. My supplementary is quite simple. At the time of providing loans, will the Ministry come forward to give priority to women applicants and to unemployed educated persons?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि यह जो हमारे पढ़े-लिखे युवक बेकार हैं, इनके लिए अलग से एक हमारी योजना चल है जिसको हम पी॰ एम॰ आर॰ वाई॰ कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के आधार पर 22 लाख यूनिट्स की स्थापना की गई है। जिसमें लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी हमने दिया है और 34 लाख लोगों को हमने इसमें रोजगार दिया है। मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि महिलाओं के प्रति, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सरकार मदद करें। महोदय, सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है।

श्री रुद्रनारायण पाणि: धन्यवाद सभापति महोदय। आज सबसे छोटा दिन है और मैं एक छोटा आदमी हूं तथा मेरा एक छोटा सवाल है। महोदय, एक शार्ट क्वेश्चन है। पिछले 1.5 साल के अंदर रेलवे ने कितना खादी खरीदा है और किन-किन संस्थाओं से खरीदा है? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री महावीर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, यह माननीय सदस्य उड़ीसा से आते हैं, यह बड़े विद्वान हैं, इनके अंदर वाकपटुता बहुत है, यह मैं देखता हूं। मैं अलग से इनको सूचना भिजवा दूंगा कि कितना खादी खरीदा गया है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

Investment in WI-MAX infrastructure

*427. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Bharat Sanchar Nigam Ltd. (BSNL) and MTNL are planing to invest in WI-MAX infrastructure;

(b) if so, the total investment being planned in this sector; and

(c) what are the services and applications that can be offered on WI-MAX technology?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI DAYANIDHI MARAN): (a) to (c) A Statement is laid on the table of the House.